>

Title: Regarding alleged corruption in implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Santhal Pargana of Jharkhand.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, नरेगा भारत सरकार की बड़ी महत्वकांक्षी योजना है। भारत सरकार कहती है कि इससे हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

18.01 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

लेकिन झारखंड में जो हालात हैं, नरेगा पानी की तरह जा रहा है और इसमें करप्शन है। इसमें 60 परसेंट कमीशन है। मरे हुए आदमी के नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है। जो जिले के बाहर के आदमी हैं, उनके नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है। जिस ब्रांच में नरेगा का पैसा जाता है, उस बैंक का मैनजेर भी जॉब कार्ड होल्डर है। पारा शिक्षक जॉब कार्ड होल्डर हैं। पोस्ट आफिस के जो ब्रांच मैनेजर हैं, पोस्ट आफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं, उनके नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है। मैं इस बारे में लगातार मंत्री महोदय से मिल चुका हूं। मंत्री महोदय से मिलकर मैंने चार-पांच महीने पहले पूरी नरेगा योजना, खासकर संथाल परगना मे जो देवगढ़, दुमका और गोड्डा जिला, जहां की निगरानी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं, उसके लिए मैंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी कराइये। उसमें से 20-22 एफआईआर भी हो गये हैं। एफआईआर होने के बाद आज तक कोई आदमी पकड़ा नही गया है। माननीय मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन में पूरा अधिकार केन्द्र सरकार का है और यही मंत्री महोदय प्रभावी हैं।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि नरेगा में एक अलग तरह की चोरी करने का भारत सरकार प्लान बना रही है। नरेगा, जैसे आपने देखा कि रेलवे में चला जायेगा, बीआरजीएफ में चला जायेगा, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में उसे जोड़ने की बात चल रही है। 13वें वित्त आयोग या 14वें वित्त आयोग का जो पैसा मिलेगा, वह भी इनक्लूड हो जायेगा। इससे उन योजनाओं का टेंडर नहीं होगा, क्योंकि नरेगा जिस एक्ट में लग जाता है, जिस योजना में लग जाता है, उसमें टेंडर नहीं होता। टेंडर नहीं होते, तो उसमें बिचौलिये हावी हो जाते हैं। एक अलग तरह की परम्परा स्टार्ट होने वाली है, चाहे आंगनवाड़ी बनेगा, चाहे पंचायत भवन बनेगा, चाहे रेलवे में चला जायेगा, चाहे रोड बनेगी। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सबसे पहले नरेगा की कोई भी योजना किसी के साथ नहीं जोड़ी जाये न बीआरजीएफ में, न रेलवे में, न इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में और न 13वें वित्त आयोग में जोड़ी जाये, जिससे बिचौलिये इसमें हावी न हों।

दूसरी, मेरी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। केन्द्र सरकार इसमें सीबीआई की इमीडिएट इंक्वायरी कराए और एक कमेटी बने कि नरेगा में आज तक जो योजनाएं बनी हैं, वे उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। जो अनुपयोगी योजनाएं हैं, उन सारे अधिकारियों पर, आज तक जितने लोगों ने काम किया है, जितने भी बीडीओ,सीईओ, जो भी हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाये।

मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं।